तिब्बत देश

तिब्बती यूथ कांग्रेस को तिब्बत–देश का सलाम !!!

कुछ दिन पहले तिब्बती युवा कांग्रेस ने अपनी 40वीं सालगिरह मनाई। अंग्रेजी में 'टिबेटन यूथ कांग्रेस' नाम की वजह से यह संगठन 'टीवाईसी' के नाम से ज्यादा लोकप्रिय है। तिब्बती शरणार्थी समाज में इस संगठन की अब तक की भूमिका को देखते हुए कहना उचित होगा कि जब भी तिब्बती आजादी के संघर्ष का इतिहास लिखा जाएगा तब इस संघर्ष में में टीवाईसी की भूमिका लगभग वही स्थान और सम्मान पाएगी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के कांग्रेस आंदोलन ने पाया।

इस संगठन ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन को एक सुनियोजित और अनुशासित ढंग से चलाने की जिम्मेदारी निभाई है बल्कि समाज के दूसरे कई क्षेत्रों में काम करने के लिए योग्य, कर्मठ और समर्पित नेताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र जैसा काम भी किया है। इसका एक सादा सा प्रमाण यह है कि भले ही तिब्बत की निर्वासन सरकार और निर्वाचित संसद के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली पद हों या अलग–अलग क्षेत्रों में काम करने वाले तिब्बती स्वयंसेवी संगठन, आज जिम्मेदारी भरे स्थान पर बैठे लगभग हर तिब्बती की सामाजिक ट्रेनिंग में टीवाईसी की महत्वपूर्ण भूमिक रही है।

टीवाईसी का गठन 7 अक्तूबर 1970 के दिन हुआ था। यह अवसर ऐसा था जब 1959 में शुरू हुए निर्वासन की भौतिक त्रासदी से तिब्बती शरणार्थी समाज कुछ उबरने लगा था और एक दीर्घकालिक रणनीति की ओर समाज ने ध्यान देना शुरू किया था। यही वह अवसर था जब तिब्बती युवाओं की पहली पीढ़ी निर्वासन में आधुनिक शिक्षा और अपने मेजबान देशों की भाषाओं के बूते पर बाहरी दुनिया के साथ एक सक्रिय संवाद शुरू करने की हालत में पहुंची थी। इसके अलावा तिब्बत की युवा पीढ़ी के लिए यह मौका अपने समाज की समस्यों के हल में हाथ बंटाने के साथ समाज को नया नेतृत्व देने और अपने देश की खोई हुई आजादी को फिर से हासिल करने के लिए एक दीर्घकालिक संघर्ष शुरू करने का भी था।

तब से यह संगठन इन क्षेत्रों में लगा हुआ है। इसे टीवाईसी के नेतृत्व की सफलता कहना होगा कि पिछले लगभग चार दशक में यह संगठन तिब्बती शरणार्थी समाज का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय संगठन बन कर उभरा है। आज टीवाईसी 12 देशों में सक्रिय है और उसकी 85 क्षेत्रीय शाखाओं में सदस्यों की संख्या 35 हजार है। केवल डेढ़ लाख सदस्यों वाले शरणार्थी समाज में सदस्यों की यह प्रभावशाली संख्या दिखाती है कि तिब्बती समाज पर इसकी पकड़ कितनी गहरी है।

पिछले चार दशक में टीवाईसी ने कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तिब्बती समाज को जाग्रत किया है और नेतृत्व दिया है। कई अवसरों पर केवल अपने बूते पर और कई बार अन्य तिब्बती संगठनों के साथ मिलकर ऐसे अनशन और शांति–यात्रा आंदोलन चलाए गए जो विश्व जनमत का तिब्बत के प्रति ध्यान खींचने में बहुत कामयाब रहे। इनमें दिल्ली में 1977 में सं.राष्ट्र कार्यालय के सामने की भूख हड़ताल, 1980 में भूटान में तिब्बती शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए किया गया अनशन, 1998 में 49 और 18 दिन की भूख हड़ताल तथा 1999 में जेनेवा में 26 दिन की और न्यूयार्क में सं.राष्ट्र मुख्यालय के सामने 30 दिन की भूख हड़ताल को राजनीतिक क्षेत्रों में आज सम्मान से याद किया जाता है। 2008 में तिब्बती संगठनों के 'बिना जल, बिना भोजन' वाले नौ–नौ दिन तक तीन टीमों के निर्जल अनशन ने गांधीवादी सत्याग्रह का एक नया रूप पेश किया था।

अपने चार दशक के कार्यकाल में टीवाईसी का व्यक्तित्व लगातार निखरा है। क्षेत्रीय इकाइयों से लेकर केंद्रीय कार्यकारिणी तक हर स्तर पर गुप्त मतदान से होने वाले चुनावों के कारण संगठन के नेतृत्व में निरंतर बदलाव आता रहा है और लोकतांत्रिक कार्यशैली ने भी इस संगठन में लगातार ताजगी को बनाए रखा है।

इस संगठन की एक और प्रभावशाली विशेषता यह है कि तिब्बत की निर्वासन सरकार को चलाने के लिए संसद और प्रधानमंत्री पद के लिए होने वाली चुनावी राजनीति से इसने शुरू से ही बाहर रहने का रास्ता चुना है। इसका एक परिणाम यह हुआ है कि टीवाईसी का सामाजिक–राजनीतिक आधार पूरे समाज तक फैला हुआ है। इस विस्तार ने उसे एक सर्वमान्य संगठन के रूप में व्यापक सम्मान और प्रभाव दिया है। यही कारण है कि टीवाईसी द्वारा उठाए जाने वाले हर मुद्दे को न केवल तिब्बती शरणार्थी समाज में बल्कि तिब्बत के सवाल में रुचि रखने वाले हर बाहरी संगठन और विशेषज्ञ गंभीरता से लेते हैं।

लेकिन इधर कुछ साल से तिब्बत की निर्वासन सरकार और तिब्बती युवा कांग्रेस के रिश्तों में अच्छा–खासा तनाव पैदा हो गया है। तिब्बत से चीन के कब्जे को हटाकर तिब्बत के वास्ते 'राग्ज़ेन' (पूर्ण तिब्बती स्वतंत्रता) के पुराने घोषित लक्ष्य को समर्पित टीवाईसी अब दलाई लामा के नेतृत्व वाली तिब्बत की निर्वासन सरकार की उस नई चीन नीति से पूरी तरह असहमत है जिसमें दलाई लामा ने चीन से 'पूर्ण आजादी' के बजाए केवल 'वास्तविक स्वायत्तता' पर ही संतुष्ट होने पर सहमति जताई है। टीवाईसी किसी भी हालत में 'रांग्ज़ेन' से कम पर सहमत होने को तैयार नहीं है। लेकिन इसे तिब्बती युवाओं के इस संगठन की परिपक्वता का प्रमाण माना जाना चाहिए कि अपने नेता के साथ इस गहरी नीतिगत असहमति के बावजूद युवा कांग्रेस ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा या किया जो दलाई लामा की गरिमा या तिब्बती समाज में उनके प्रति आदर के विपरीत हो। अपनी इस नीति के कारण टीवाईसी ने तिब्बती समाज और तिब्बती सरकार दोनों से समर्थन और सम्मान पाया है। इसे तिब्बती समाज में लोकतंत्र के बढ़ते प्रभाव का संकेत माना जाना चाहिए।

40वीं सालगिरह के मौके पर टीवाईसी के वर्तमान अध्यक्ष त्सेवांग रिग्ज़िन ने 7 अक्तूबर के सम्मेलन में यह बयान देकर अपने संगठन की लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचय दिया कि ''हम तिब्बती आजादी के सवाल पर परमपावन दलाई लामा की 'केवल वास्तविक स्वायत्तता' की नीति से पूरी तरह असहमत हैं .... लेकिन उनके नेतृत्व में हमारी पूरी आस्था है और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं।''

तिब्बती युवा कांग्रेस के व्यक्तित्व का एक और प्रभावकारी हिस्सा है अहिंसा में उसकी गहरी आस्था। यह आस्था ऐसे आंदोलनों में भी प्रभावशाली तरीके से उभर कर आई जिनमें छोटी सी चूक से भी आंदोलन के हिंसक होने का गंभीर खतरा था। उदाहरण के लिए पिछले कुछ साल में कम से कम ऐसे दो मौके आए जब तिब्बती युवा कांग्रेस के कई युवा कार्यकर्ता भारतीय और चीनी सुरक्षा बलों की चौकसी के बावजूद नई दिल्ली के चीनी दूतावास में घुसने में सफल रहे। इनमें से एक मौके पर तो ये कार्यकर्ता चीनी झंडा जलाने में भी कामयाब रहे। दूसरे ऐसे मौके पर ऐसे कई कार्यकर्ता दूतावास की दीवार के साथ अपनी बस को सटाकर दूतावास परिसर के भीतर तक पहुंचने में कामयाब रहे। तब भी चीनी सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की ओर से की गई हिंसा के बावजूद किसी भी तिब्बती कार्यकर्ता ने किसी तरह की जवाबी हिंसा नहीं की और अपने प्रदर्शन को केवल नारेबाजी तक सीमित रखा। बल्कि एक कार्यकर्ता ने खुद को चीनी झंडे के खंभे के साथ हथकड़ी से बांधकर सुरक्षा कर्मियों को नए धर्मसंकट में डाल दिया। उस अवसर पर भले ही चीन सरकार ने अपने प्रचार अभियान में इसे तिब्बती युवा कांग्रेस के 'आतंकवादियों' की एक 'आतंकवादी हरकत' के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसके दूतावास अधिकारियों ने स्वीकार किया कि अंदर घुस आए तिब्बतियों ने किसी कर्मचारी के खिलाफ हिंसा नहीं की।

तिब्बती आजादी को समर्पित और तिब्बती जनता, खासकर चीनी कब्जे में रहने वाली तिब्बती जनता, की राष्ट्रीय आंक्षाओं के सही प्रतिनिधि तिब्बती युवा कांग्रेस को अपने 40वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर 'तिब्बत देश' का सलाम।

– विजय क्रान्ति

नाथू ला में भारतीय और चीनी सैनिक – संशय का रिश्ता

भारत–चीन सीमा पर चीन के दुस्साहस के पीछे का खतरनाक सच

भारत की शतुरमुर्गी उदासीनता और चीन की आक्रामक कूटनीति ने भारत का संकट में डाला

– भास्कर रॉय –

पश्चिमी सेक्टर में चीन का एक लक्ष्य है पाकिस्तान होकर फारस की खाड़ी में जाने के लिए काराकोरम हाईवे का इस्तेमाल। उसकी दूसरी योजना ग्वादर से पश्चिमी चीन तक तेल और गैस की जुड़वां पाइपलाइनें बिछाने की भी है।

हालांकि भारत–चीन सीमा का अभी परिसीमन किया जाना है और वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्षों को अच्छी तरह मालूम है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहां है। इससे भारत नियंत्रित क्षेत्र में गंभीर हमलों को रुक जाना चाहिए था।

लेकिन समस्या यह है कि पिछले कुछ समय से चीन भारतीय क्षेत्र में गंभीर हमले करता आ रहा है। ये हमले लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रहे हैं जो भारत–चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर में आते हैं। चीन के इन हमलों का मकसद भारत की जमीन पर दावा करना है। पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर में वर्षों से छिटपुट हमले होते रहे हैं और भारत सरकार उनका विरोध करती रही है।

इस साल जुलाई से, भारतीय क्षेत्र पर चीनी अतिक्रमण की शैली में गुणात्मक बदलाव आया है। सो, भारतीय क्षेत्र में चट्टानों पर चीनी नारे लिखना और चीनी चरित्र छापना, दो चीनी हेलिकॉप्टरों का भारत में घुस आना, चीन निर्मित डिब्बाबंद खाना गिराना और तीन चीनी लड़ाकू विमानों का दूसरी बार भारतीय सीमा में घुस आना बहुत गंभीर बात है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

भारतीय मीडिया के एक हिस्से में खबर छपी थी कि चीनी सैनिकों की फायरिंग में भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के दो सैनिक घायल हो गए। लेकिन दोनों देशों ने इस खबर का खंडन कर दिया। ऐसे में भारत के आजाद मीडिया को अधिक जिम्मेदार बनने की जरूरत है।

चीन का नजरिया, लंबे समय से यह रहा है कि ''यदि भारत पश्चिमी सेक्टर में रियायत करता है तो चीन पूर्वी सेक्टर में रियायत करने पर विचार करेगा।'' चीनी सरकारी मीडिया और विचारक अपने देश के इस नजरिए को प्रचारित करते रहे हैं। बहरहाल, चीन ने अपने नजरिए के बारे में विस्तार से कभी कुछ नहीं कहा। भारत और चीन के बीच दोनों सेक्टरों के नक्शों का आदान–प्रदान लंबित पड़ा हुआ है। लिहाजा यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहां से शुरू हो रही है और कहां खत्म।

चीन के लिए अपने दक्षिण–पश्चिम रणनीतिक विस्तार के संदर्भ में पश्चिमी सेक्टर का महत्व बढ़ गया है। वह पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चिन के 38000 वर्ग किमी इलाके पर काबिज है जबकि उस पर भारत का दावा रहा है। चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाला ट्रांस–नेशनल काराकोरम हाईवे भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पाकिस्तान में प्रवेश करता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत अपना दावा जताता रहा है।

पाकिस्तान ने भारतीय दावे की अनदेखी करते हुए 1963 में एक समझौते के तहत अपने कब्जे वाले कश्मीर का 5000 वर्ग किमी भूभाग चीन को दे दिया।

अक्साई चिन चीन को तिब्बत होकर शिंजियांग तक भूतल परिवहन भी मुहैया कराता है। शिंजियांग के उइगुर मुसलमान इस प्रांत पर चीनी कब्जे का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल, यह सड़क चीन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीनी सैनिक इसके जरिए शिंजियांग में आसानी से आवाजाही कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें शिंजियांग में मध्य एशिया से लगने वाली सीमा तक जाने में भी सहूलियत हो गई है।

चीन पश्चिमी सेक्टर में दो महत्वपूर्ण कारणों से अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। पहला, है पाकिस्तान होकर फारस की खाड़ी में जाने के लिए काराकोरम हाईवे का इस्तेमाल। इस हाईवे के कारण चीन और फारस की खाड़ी की दूरी कम हो जाएगी। चीन पाकिस्तान के ग्वादर में पहले ही एक बंदरगाह का निर्माण कर चुका है और काराकोरम हाईवे उससे जुड़ा हुआ है। उसकी योजना ग्वादर से पश्चिमी चीन तक तेल और गैस की जुड़वां पाइपलाइनें बिछाने की भी है। यह एक कड़ी चुनौती है लेकिन इन पाइपलाइनों

का बिछ जाना इंजीनियरिंग की महान उपलब्धि होगी। इसके पहले चीन तिब्बत के ऊबड़–खाबड़ पठार के आर–पार रेलवे लाइन बिछाने का करिश्मा कर दिखाया है।

चीन के रणनीतिक महत्व के दो अन्य उद्देश्य भी हैं। पहला, भारतीय क्षेत्र में चीनी सीमा का अधिक से अधिक विस्तार करना। दूसरा,चीनी फौज को भारतीय भूमार्ग के बेहद करीब लाना और लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी हिस्से को बाकी भारत से काटकर लद्दाख को कमजोर बनाना। यह कुछ–कुछ वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने 1999 में करगिल में करने की कोशिश की थी। उसने कश्मीर को जोड़ने वाले भूमार्ग को काटने की कोशिश की थी।

चीन ने सिक्किम के साथ लगी सीमा पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। 'फिंगर पॉइंट' क्षेत्र, जहां चीनी सैनिक बार–बार अतिक्रमण कर रहे हैं, दोनों पक्षों के लिए सामरिक महत्व का है। 'फिंगर पॉइंट' सिक्किम और तिब्बत दोनों की सीमाओं के भीतर है।

हालांकि चीन ने 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी की यात्रा के दौरान सिक्किम को भारत का अंग मान लेने का दिखावा किया था। लेकिन हकीकत यह है कि उसने सिक्किम को भारत का अंग कभी नहीं माना। प्रधानमंत्री वाजपेयी और भारत सरकार चीन की इस चाल में आ गए कि यदि भारत तिब्बत को पूरी तरह चीन का अंग मान लेगा तो चीन भी सिक्किम पर भारत की प्रभुसत्ता को मान्यता दे देगा।

भारत ने तो तिब्बत को चीन का अंग मान लिया लेकिन चीन ने सिक्किम से संबंधित अपना वादा पूरा नहीं किया। वह हमेशा यही कहता रहा कि सिक्किम के मामले में कोई सीमा विवाद नहीं है। सिक्किम का मुद्दा भारत पर दबाव बनाने की चाल है और वह कभी भी ज्वलंत मसला बन सकता है। विवाद के नए क्षेत्र खोलना चीन की खतरनाक चाल है।

पूर्वी सेक्टर में, चीन 90,000 वर्ग किमी भूभाग पर अपना दावा करता है। यानी वह भारत के साथ सीमा विवाद और क्षेत्र विवाद को जिंदा रखने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए समूचे अरुणाचल प्रदेश का इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने ठीक यही किया जब उसने अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्य के लिए एशियाई विकास बैंक से भारत को मिलने वाले ऋण में अड़ंगा लगाने की कोशिश की।

भारत ने स्पष्ट षब्दों में कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेष उसका अंग है और उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हां, आबादी को छेड़े बिना सीमा पर छोटा–मोटा सामंजस्य बैठाया जा सकता है।

सीमा मसले को सुलझाने की रूपरेखा पर भारत–चीन के बीच 2005 में हुए समझौते में एक धारा यह है कि बसी हुई आबादी को छेड़ा नहीं जाएगा। हालांकि समझौता संयुक्त रूप से तैयार किया गया था, लेकिन चीन इस धारा का उल्लंघन कर रहा है। चीन का लक्ष्य तावांग को हासिल करना है क्योंकि वह उसे महान रणनीतिक महत्व का मानता है।

चीन का एक तर्क यह है कि दलाईलामा तावांग में पैदा हुए थे, इसलिए तिब्बती उस जगह की बहुत कद्र करते हैं। उसका कहना है तिब्बतियों की भावनाएं तावांग से जुड़ी हैं, लिहाजा उसे तिब्बत का अंग होना चाहिए। चीन का यह तर्क खोखला है। इतिहास को देखें तो परम पावन व्यक्ति अपने जन्मस्थान को छोड़कर दूसरी जगह बस गए थे।

तावांग भारत, भूटान और तिब्बत की संधि पर बसा हुआ है। तवांग पर कब्जा हो जाने से चीन न केवल भूटान की पूर्वी सीमा पर, बल्कि सिलिगुड़ी में चिकन नेक नाम की पट्टी के किनारे भी अपनी फौज तैनात कर देगा। यह पट्टी पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है।

चीनी फौज युद्ध के समय में चिकन नेक पट्टी को आनन–फानन में काट सकती है क्योंकि ढाल के नीचे का कॉरिडोर कमजोर है।

चीन की योजना तिब्बत में रेलवे को पूर्वी सेक्टर में भारतीय सीमा पर स्थित शिगात्से तक ले जाने की है। इससे चीनी फौज को लामबंद करने में बहुत मदद मिलेगी। इस बात को कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि बीजिंग अपने 'फॉरवर्ड डिफेंस' के सिद्धांत के तहत भारत–हिमालय क्षेत्र को दक्षिण की तरफ ढकेल रहा है।

गौरतलब है कि चीन भारत से लगी अपनी सीमाओं की किलेबंदी करता रहा है। लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई करने से बचता रहा है।

भारत ने शायद ही किसी स्थायी ढांचे का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों में भारतीय गश्ती दल उस इलाके में भी नहीं जाते जिस पर कि भारत दावा करता है। कुछ इलाकों में वे बिना किसी हथियार के जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अन्य हिस्सों में केवल नागरिक गश्त लगाते हैं।

कहा जाता है कि यह चीन को न भड़काने की सरकार की नीति है। दरअसल, भारतीयों ने भारत–चीन रिश्तों में केवल अपनी कमजोरी का ही प्रदर्शन किया है जिसका चीनियों ने पूरा–पूरा लाभ उठाया है।

रीडिफ.कॉम से साभार

तावांग भारत, भूटान और तिब्बत की संधि पर बसा हुआ है। तवांग पर कब्जा हो जाने से चीन न केवल भूटान की पूर्वी सीमा पर, बल्कि सिलिगुड़ी में चिकन नेक नाम की पट्टी के किनारे भी अपनी फौज तैनात कर देगा। यह पट्टी पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। चीनी फौज युद्ध के समय में चिकन नेक पट्टी को आनन–फानन में काट सकती है क्योंकि ढाल के नीचे का कॉरिडोर कमजोर है।

एक पूर्व तिब्बती बंदी की दर्दनाक यादें

चीनी जेल में 27 साल बिताने के बाद आज भी आजादी के संघर्ष में आगे

–मयंक अग्रवाल–

धर्मशाला चीनी अधिकारियों द्वारा उन्हें जेल से रिहा किए हुए दो दशक से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन जेल की दर्दनाक यादें अभी भी उन्हें परेशान करती हैं। उनका नाम है अम्मा आदि। अस्सी वर्षीया तिब्बती महिला अम्मा आदि भारत में रहती हैं और अपना ज्यादातर समय प्रार्थना में बिताती हैं।

अम्मा आदि कहती हैं, ''मैंने स्वतंत्र तिब्बत को देखा है। मैंने अपने संघर्ष के दौरान चीनी फौज की क्रूरता भी देखी है। चीनी फौज ने 1958 में मुझे और संघर्श में शामिल 300 अन्य महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आदी पूर्वी तिब्बत की रहने वाली हैं।

वे उस तिब्बती संघर्ष में शामिल थीं जो 1951 में तिब्बत पर चीन के जबरन कब्जे के बाद 1959 में चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ तिब्बती विद्रोह बनकर फूटा था। चीनी फौज ने विद्रोह को कुचल दिया और तिब्बत के धार्मिक शासक 14वें दलाई लामा सहित हजारों तिब्बतियों ने तिब्बत छोड़कर भारत तथा दुनिया के अन्य हिस्सों में शरण ली।

फिलहाल, निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की संख्या 140,000 से अधिक है। इनमें से लगभग 100,000 तिब्बती भारत में हैं।

बीस साल पहले जब 40 तिब्बती शरणार्थियों का एक नया दस्ता, जिनमें नौ पूर्व राजनैतिक बंदी थे, धर्मशाला पहुंचा तो अम्मा आदि भी उनमें थीं। ध र्मशाला (हिमाचल प्रदेश) तिब्बत की निर्वासन सरकार का मुख्यालय है।

अम्मा आदि जब मुझे अपनी कहानी सुना रही थीं तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, ''जेल की स्थिति अमानवीय थी। हमें कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था और अगर दिया भी जाता था तो बहुत कम। इसका परिणाम यह हुआ कि डेढ़ साल के भीतर 150 महिलाएं मर गईं। हममें से कई महिलाओं ने तो चमड़े के जूते के सोल भी खा डाले। तीन साल के बाद हममें से केवल चार महिलाएं बचीं। जब हमें तिब्बत की एक दूसरी जेल में ले जाया जा रहा था तो मैंने शवों का एक ढेर देखा। मैं कांप उठी।''

जेल की स्थिति अमानवीय थी। हमें कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था और अगर दिया भी जाता था तो बहुत कम। इसका परिणाम यह हुआ कि डेढ़ साल के भीतर 150 महिलाएं मर गईं। हममें से कई महिलाओं ने तो चमड़े के जूते के सोल भी खा डाले। तीन साल के बाद हममें से केवल चार महिलाएं बचीं। जब हमें तिब्बत की एक दूसरी जेल में ले जाया जा रहा था तो मैंने शवों का एक ढेर देखा। मैं कांप उठी।

अम्मा को 27 साल जेल में रहने के बाद 1985 में रिहा किया गया। उन्हें बंदी बनाए जाने से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। चीनी फौज जब आदी को ले जा रही था तो उनका बेटा नदी में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। उनकी बेटी को उनके मित्र ने पाला–पोसा।

चीनी फौज ने उन्हें इस शर्त पर रिहा किया कि वे जेल में अनुभवों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी।

उन्होंने इस संवाददाता को बताया, ''मेरी बेटी ने मुझे अपने साथ रहने को कहा। लेकिन मैं दुनिया को तिब्बत में चीनी हुकूमत की स्थिति, अमानवीय बर्ताव और तिब्बती राजनैतिक बंदियों की दुर्दशा के बारे में बताना चाहती थी।

अम्मा आदि ने 1986 और 1987 में भारत आने की कोशिश की लेकिन विफल रहीं। अंततः वे 1988 में भारत पहुंची। अम्मा यहां तिब्बत के पूर्व शासक और सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मिलीं। परमपावन दलाई लामा ने उन्हें दुनिया को 'सचाई' बताने कर सलाह दी। अम्मा आदि ने इसके बाद ''वॉयस दैट रिमेंस'' नाम से एक किताब लिखी। इसमें उन्होंने अपने अनुभवों का ब्योरा दिया है।

आजकल वे अपने दूसरे पति के साथ धर्मशाला के मकलेडगंज में रहती हैं और अपना समय प्रार्थना में बिताती हैं। अम्मा आदि उन सैकड़ों पूर्व राजनैतिक बंदियों में से एक हैं जो निर्वासन में भारत में रह रहे हैं। तिब्बती राजनैतिक बंदियों के कल्याण के लिए काम करने वाले गु–चु–सुम आंदोलन के नावांग वोबर ने कहा, ''हमारे यहां लगभग 500 पूर्व राजनैतिक बंदी पंजीकृत हैं। ये सभी भारत में रहते हैं। कई ऐसे भी हैं जो हमारे साथ पंजीकृत नहीं हैं।''

खुद राजनैतिक बंदी रहे वोबर ने कहा, ''तिब्बत में अभी भी हजारों तिब्बती जेल में सड़ रहे हैं। उन्हें कुछ वर्ष के कारावास से लेकर मौत तक की सजा मिली हुई है। उनमें कई ऐसे हैं जो अपने जीवन के दो दशक से अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं।''

वोबर ने आगे कहा, ''मार्च 2008 के विद्रोह के दौरान हजारों तिब्बतियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें 30 प्रतिशत महिलाएं थीं। इस बार विद्रोह में युवकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अस्सी प्रतिशत प्रदर्शनकारी 18–35 आयुवर्ग के थे। हमारे लोग अपने ही देश में कष्ट उठा रहे हैं। उन्होंने कभी दलाई लामा को देखा तक नहीं।''

आईएएनएस से साभार

तिब्बत में बसाई जा रही चीनी आबादी की बाढ़ में तिब्बती अस्तित्व खतरे में

संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में तिब्बत में चीनी उपनिवेशवाद का मुद्दा उठाया गया

तिब्बत.नेट, 23 सितंबर श्री तेनजिंग कायता ने संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में 'सोसाइटी फॉर थ्रेटेंड' की तरफ से बोलते हुए परिषद का ध्यान तिब्बत की स्थिति की तरफ खींचा। उन्होंने शिंनजियांग और तिब्बत में मानवाधिकारों पर चिंता व्यक्त करने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के बयान पर भी कटाक्ष किए। गौरतलब है कि उच्चायुक्त एन. पिल्लै ने पिछले हफ्ते परिषद को संबोधित करते हुए कहा था कि चीनी अधिकारियों को ''कानून–व्यवस्था बनाए रखते समय मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए'' और ''भेदभाव तथा अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा में विफलता वाली घटनाओं के मूल कारणों का पता लगाना चाहिए।'' तेनजिन के अनुसार चीन पर ऐसी लफ्फाजी का कोई असर नहीं पड़ता।

श्री तेनज़िन ने तिब्बत में चीनी से लाकर हान लोगों को बसाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे तिब्बती संस्कृति को खतरा पैदा हो गया है। चीन के सरकारी प्रकाशनों के अनुसार, 1990–95 के बीच तिब्बती पठार पर कुल आबादी 10,102,000 थी जिसमें महज 48 प्रतिशत यानी 4,821,500 तिब्बती थे। श्री तेनज़िन ने चेतावनी दी कि यदि यह जारी रहा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने हस्तक्षेप नहीं किया तो तिब्बती लोग चीन से लाकर बसाए गए अधिवासियों के समुद्र में खो जाएंगे और तिब्बत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत खत्म हो जाएगी। उन्होंने परिषद का ध्यान तिब्बती बंजारों के पुनर्वास से संबंधित चीन सरकार के कार्यक्रम की तरफ भी खींचा। पूरे तिब्बत में स्वछंद और मुक्त जीवन जीने वाले लाखों बंजारों को चीन सरकार खास तौर से बनायी जा रही कालोनियों में जबरन बसा रही है।

संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष प्रतिनिधियों ने 3 अक्तूबर 2007 को चीन से संबंधित अपनी संयुक्त जांच में कहा था, ''इन पुनर्वास कायक्रमों से तिब्बती इलाकों की पारंपरिक जीवनशैली पर प्रतिकूल असर पड़ा है। पारंपरिक तिब्बती जीवन के ताने–बाने पर इनका सीधा प्रभाव पड़ा है और वहां रहने वाले समुदायों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इन नीतियों के क्रियान्वयन से आज तिब्बती संस्कृति और धार्मिक पहचान खतरे में पड़ गई है।''

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के उप स्थायी प्रतिनिधि श्री डगलस ग्रिफिथ्स ने कहा, ''हमने चीन के शिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र की हाल की घटनाओं और तिब्बती इलाकों में पिछले साल फैली अशांति पर करीबी नजर रखी। हम चीनी अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे व्यवस्था बहाल करते समय चीन के सभी नागरिकों की सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों का ध्यान रखें और वैध शिकायतों का समाधान निकालें।''

दोपहर बाद, संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत से संबंधित चीनी शिक्षा नीति पर चर्चा के लिए एक समानांतर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं में तिब्बत के पूर्व मिडिल स्कूल शिक्षक श्री लोबसांग निमा लांगमो गोम्बात्सांग और श्री त्सेतेन एस. छोएक्यापा शामिल थे। जिनेवा (स्विटजरलैंड) में तैनात श्री छोएक्यापा मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों में परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि हैं।

लांगमो गोम्बात्सांग ने बताया कि तिब्बत से संबंधित चीन की शिक्षा नीति का विकास किस तरह हुआ। उन्होंने कहा कि उनके स्कूल के पाठ्यक्रम में तिब्बती भाषा शामिल नहीं थी। हर विषय चीनी भाषा में पढ़ाया जाता था। स्कूल में रहते हुए कई अन्य तिब्बती छात्रों की तरह वे भी तिब्बती भाषा में अपना नाम लिखना नहीं जानते थे। श्री लांगमो गोम्बातसांग के मुताबिक, जब स्वर्गीय पंचेन लामा ने देखा कि तिब्बतियों को तिब्बती भाषा में शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है तो उन्होंने अपने प्रयासों से यह सुनिश्चित किया कि स्कूल के पाठ्यक्रम में तिब्बती भाषा पर अधिक ध्यान दिया जाए। श्री लांगमो गोम्बातसांग ने कहा कि चीनी अधिकारी तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म को तिब्बत में चीन की निरंकुश हुकूमत के लिए खतरा मानते हैं। पूरे तिब्बत में लाखों की संख्या में चीनियों को लाकर बसाने से अब ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि चीनी भाषा न जानने वाले स्थानीय तिब्बतियों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है।

परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि श्री त्सेतेन एस. छोएक्यापा ने तिब्बत में मानवाधिकारों और राजनैतिक स्थिति की पूरी तस्वीर पेश की। कार्यक्रम में एक वृत्तचित्र ''तिब्बत : मर्डर इन द स्नो'' भी दिखाई गई। यूएनपीओ के प्रतिनिधि श्री नावांग सी. द्राक्यांगपोन ने कार्यक्रम के मॉडरेटर के रूप में इसका संक्षिप्त परिचय दिया। कई गैरसरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र में विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

लांगमो गोम्बातसांग ने कहा कि चीनी अधिकारी तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म को तिब्बत में चीन की निरंकुश हुकूमत के लिए खतरा मानते हैं। पूरे तिब्बत में लाखों की संख्या में चीनियों को लाकर बसाने से अब ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि चीनी भाषा न जानने वाले स्थानीय तिब्बतियों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है।

झूठे इतिहास से झूठा प्रचार

तोक्यो में चीन की तिब्बत प्रदर्शनी पर जापानियों और तिब्बतियों ने विरोध जताया

तिब्बत कस्टम, 19 सितंबर तोक्यो उएनो रॉयल म्युजियम में आयोजित चीनी प्रदर्शनी ''तिब्बतः ट्रेजर्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड'' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए लगभग 100 जापानी और तिब्बती तोक्यो उएनो ताकेचो पार्क में इकट्ठा हुए। प्रदर्शनी का आयोजन उएनो रॉयल म्युजियम और कुछ जापानी मीडिया तथा वाणिज्यिक संस्थानों ने चीन सरकार के सहयोग से किया है।

प्रदर्शनी में शामिल वस्तुएं और दस्तावेज इस तरह पेश किए गए हैं जिनसे लगे कि चीन सरकार सचमुच तिब्बती संस्कृति की संरक्षक है। ये वस्तुएं तिब्बती मठों और निजी घरों से या तो चुराई गई हैं या फिर जब्त की गई हैं। म्युजियम का उद्देश्य ऐसी चीजों के बारे में सच बताना है जिनसे लोग प्रेरणा ग्रहण करें। इसलिए म्युजियम ने प्रतिष्ठित जापानी संग्रहालय के रूप में तिब्बतियों के प्रति न्याय नहीं किया है।

जापानी समर्थकों और तिब्बतियों का कहना है कि चीन सरकार ने जापानी जनता और दुनिया को गुमराह करने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। चीन सरकार दुनिया को विश्वास दिलाना चाहती है कि वह तिब्बती धार्मिक संस्कृति की संहारक नहीं, बल्कि वास्तविक संरक्षक है।

विरोध प्रदर्शन का आयोजन इंटरनेशनल एलायंस अगेंस्ट द तिब्बत एक्जीबिशन की जापानी शाखा ने तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स और तिब्बती समुदाय के सहयोग से किया। जापान और पूर्वी एशिया में परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि श्री ल्हाक्पा त्शोको ने तिब्बती उद्देश्य के समर्थन के लिए विरोध प्रदर्शन के आयोजकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दुनिया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, वहां के 6,000 मठों को नष्ट किया जा रहा है और तिब्बत की शांतिपूर्ण एवं धार्मिक जनता को यातनाएं दी जा रही हैं।

श्री त्शोको ने कहा, ''प्रदर्शनी में शामिल वस्तुएं और दस्तावेज इस तरह पेश किए गए हैं जिनसे लगे कि चीन सरकार सचमुच तिब्बती संस्कृति की संरक्षक है। ये वस्तुएं तिब्बती मठों और निजी घरों से या तो चुराई गई हैं या फिर जब्त की गई हैं। म्युजियम का उद्देश्य ऐसी चीजों के बारे में सच बताना है जिनसे लोग प्रेरणा ग्रहण करें। चूंकि चीन सरकार की यह प्रदर्शनी इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी है, इसलिए म्युजियम ने प्रतिष्ठित जापानी संग्रहालय के रूप में तिब्बतियों के प्रति न्याय नहीं किया है।''

परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि के भाषण का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शनी के विरोध में और पिछले साल 10 मार्च से तिब्बत में मारे गए तिब्बतियों के सम्मान में काले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने मुख्य तोक्यो उएनो पार्क से प्रदर्शनी स्थल तक तिब्बती झंडों और बैनरों के साथ मौन जुलूस निकाला। जुलूस जब शहर की मुख्य सड़क से गुजर रहा था तो उसके आयोजक लाउडस्पीकर पर जुलूस के उद्देश्य और तिब्बत की स्थिति के बारे में लोगों को बता रहे थे। राहगीर समर्थन में अपने हाथों को उठाकर लहरा रहे थे।

तोक्यो उएनो पार्क पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने 'फ्री तिब्बत' के नारे लगाए। इसके बाद पार्क स्थित तोक्यो एक्जीबिशन हॉल में तिब्बत पर एक संगोष्ठी हुई। इसका आयोजन एक तिब्बत सपोर्ट ग्रुप तिब्बत आर्ट फोरम ने किया था। परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि ल्हाकपा त्शोको ने संगोष्ठी में तिब्बत की स्थिति के बारे में बताया और जापानी जनता से अपील की कि वे तिब्बत में न्याय और आजादी का समर्थन करें। आयोजकों के प्रतिनिधि श्री मियोशी ने प्रदर्शनी को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने सबूत के रूप में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र भी किया।

संगोष्ठी के मुख्य वक्ता, तोक्यो युनिवर्सिटी के प्रो. तजाकी कुनिहिको ने तिब्बत के इतिहास और उसकी बौद्ध संस्कृति पर रोशनी डाली। उन्होंने तिब्बत राष्ट्र की स्वतंत्र प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि न्याय और आजादी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आजाद देश में रहने वाले लोगों को तिब्बतियों के संघर्ष का समर्थन करना चाहिए और हर तरह से मदद करनी चाहिए। तिब्बती इतिहास और संस्कृति में भी लोगों को दिलचस्पी लेनी चाहिए। प्रो. कुनिहिको के भाषण के बाद सवाल–जवाब का सत्र हुआ।

संगोष्ठी में भाग लेने वाले लोगों ने जुलूस में शामिल होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जुलूस में भाग लेने पर प्रदर्शनी के आयोजकों और उनके जापानी सहयोगियों के बारे में उनकी राय बदल गई है। कइ लोगों ने कहा कि म्युजियम को तिब्बती इतिहास के बारे में भी बताना चाहिए और व्याख्यान देने के लिए परमपावन के प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए। कुछ जापानियों ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि स्वतंत्र देश माने जाने वाले जापान में इस तरह की चीजें हो रही हैं। बताया जाता है कि प्रदर्शनी अगले साल जनवरी तक चलेगी। प्रदर्शनकारियों और विभिन्न तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के प्रतिनिधियों ने ऐलान किया है कि प्रदर्शनी के दौरान किसी न किसी तरह का विरोध लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। जुलूस में शामिल लोगों ने इस ऐलान का स्वागत किया।

तिब्बत में चीन की उपनिवेशवादी घुटन से बचने के लिए पलायन अभी भी जारी

एक किशोर बालक ने तिब्बत में जारी हिंसा शिक्ष की बदहाली की कहानी सुनाई

धर्मशाला, 19 सितंबर भारत में शरण मांगने वाला एक युवा तिब्बती लड़का चीनी अधिकारियों के अत्याचार की कहानी सुनाते हुए रो पड़ा। जमयांग नाम के इस सोलह वर्षीय लड़के ने धर्मशाला पहुंचने पर अपने अनुभव के बारे में बताया। वह 2 सितंबर को धर्मशाला के पास मकलोडगंज स्थित तिब्बती रिसेप्शन सेंटर में पहुंचा था। उसने ल्हासा से काफी दूर अपने घर के पड़ोस में चीनी अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में बताया।

जमयांग ने कहा, ''मेरा घर ल्हासा से बहुत दूर है, फिर भी तमाम चीनी सैनिक और चीनी अधिकारी हमारे इलाके में आते रहते हैं। पिछले साल जब हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब उन्होंने हमारे सिर पर लोहे की छड़ों से वार किए।''

जमयांग ने बताया कि उसके धर्मशाला आने का उद्देश्य बेहतर शिक्षा ग्रहण करना और दलाई लामा से मिलना है। उसके किसान माता–पिता ने उसकी शिक्षा के लिए उसे नेपाल होकर भारत भेजा, यह जानते हुए भी कि उनके बेटे को कई दिनों तक बिना खाना के रहना पड़ सकता है। यही नहीं, यात्रा में उसकी जान भी जा सकती थी।

जमयांग अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। वह हाल में धर्मशाला आए 40 से अधिक तिब्बतियों के एक जत्थे में शामिल था। उसका इरादा अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करना है। जमयांग महज पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़कर इतनी दूर आया है। वह अब बीर स्कूल में दाखिला लेगा। बीर स्कूल उन कई स्कूलों में से एक है जिन्हें निर्वासन सरकार ने यहां शुरू किया है।

चीनी हुकूमत के मातहत पिस रहे तिब्बत की परिस्थितियों के कारण जामयांग वहां स्कूल नहीं जा पाता था। अपनी 40 दिन लंबी यात्रा के बारे में याद करते हुए उसने बताया कि वह मुश्किलों से भरी हुई थी। उसने कहा, ''मैं पहले ल्हासा गया। फिर वहां से हिमालय को पार कर नेपाल सीमा पर पहुंचा। लेकिन नेपाल सीमा पर सुरक्षा बहुत कड़ी थी और तिब्बत–नेपाल सीमा को पार करना बहुत मुश्किल था। मैं तीन दिनों तक बिना कुछ खाए रहा।''

लेकिन नेपाल पहुंचने के बाद हालत बेहतर हो गई। एक महीना बाद कुछ शरणाथयों को, जिनमें जमयांग सहित 12 किशोर भी थे, एक विशेष बस से नई दिल्ली और फिर धर्मशाला भेजा गया।

निर्वासन सरकार तिब्बती बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है। जहां उसके कुछ स्कूल भारत सरकार के नियंत्रण में हैं, वहीं अन्य स्कूलों का संचालन तिब्बत चिल्ड्रन विलेज (टीसीवी) सरीखे स्वतंत्र संगठन करते हैं। भारत, नेपाल और भूटान में शरणार्थियों के लिए बनाए गए 82 स्कूलों में लगभग 27,000 छात्र पढ़ते हैं। शिक्षा के जरिए तिब्बती संस्कृति के संरक्षण पर बहुत जोर दिया जाता है।

निर्वासन सरकार के अंतरराष्ट्रीय संबंध सचिव सोनम एन. दागपो ने कहा, ''हम तिब्बती भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर जोर देते हैं। हमारे स्कूलों में सीबीएससी के पाठ्यक्रम चलते हैं और हम तीन भाषाएं––तिब्बती, हिंदी तथा अंग्रेजी––पढ़ाते हैं। शुरू में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, लेकिन अब हमने तिब्बती भाषा कर दिया है। फिलहाल पांचवीं कक्षा तक तिब्बती भाषा में शिक्षा दी जाती है। इसे बढ़ाकर दसवीं कक्षा तक किया जाएगा। हम चाहते हैं कि तिब्बती बच्चे अपनी संस्कृति न भूलें।''

भारत ने पिछले पांच दशकों से तिब्बती समुदाय और उनके आध्यात्मिक नेताओं को शरण दी है। सो, तिब्बती समुदाय 2009 को भारत के प्रति आभार वर्ष के रूप में मना रहा है। उसका नारा हैः ''धन्यवाद भारतः निर्वासन में 50 साल''।

टीसीवी के शिक्षा निदेशक तेंजिंग सांगपो ने कहा, ''हमारे बच्चों के लिए शिक्षा सर्वोच्च वरीयता है। हम उन्हें केवल शिक्षा नहीं मुहैया करा रहे हैं, बल्कि उनमें अपने देश के प्रति उम्मीद भी जगा रहे हैं। यदि वे शिक्षित बनेंगे तो अपने देश के लिए काम करेंगे।

टीसीवी में हर साल लगभग 800–900 बच्चे आते थे। लेकिन पिछले साल तिब्बत में दमन के बाद से वहां केवल 150 बच्चे आए।

सांगपो ने कहा, ''हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उसने हमारा पूरा समर्थन किया है और आज हमारे छात्र बहुत सफल हैं। भारत हमारे लिए दूसरा घर बन गया है और तिब्बतियों ने भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह अपना लिया है।

हमारे कई छात्र आज डॉक्टर, प्रशासक, इंजीनियर, पोस्ट–ग्रेजुएट शिक्षक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। भारत में शिक्षित यह पीढ़ी अब न केवल तिब्बत की निर्वासन सरकार को चला रही है बल्कि उसने निर्वासन में तिब्बती संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को फिर से जीवित कर लिया है।

निर्वासन सरकार तिब्बती बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है। जहां उसके कुछ स्कूल भारत सरकार के नियंत्रण में हैं, वहीं अन्य स्कूलों का संचालन तिब्बत चिल्ड्रन विलेज (टीसीवी) सरीखे स्वतंत्र संगठन करते हैं। भारत, नेपाल और भूटान में शरणार्थियों के लिए बनाए गए 82 स्कूलों में लगभग 27,000 छात्र पढ़ते हैं। शिक्षा के जरिए तिब्बती संस्कृति के संरक्षण पर बहुत जोर दिया जाता है।

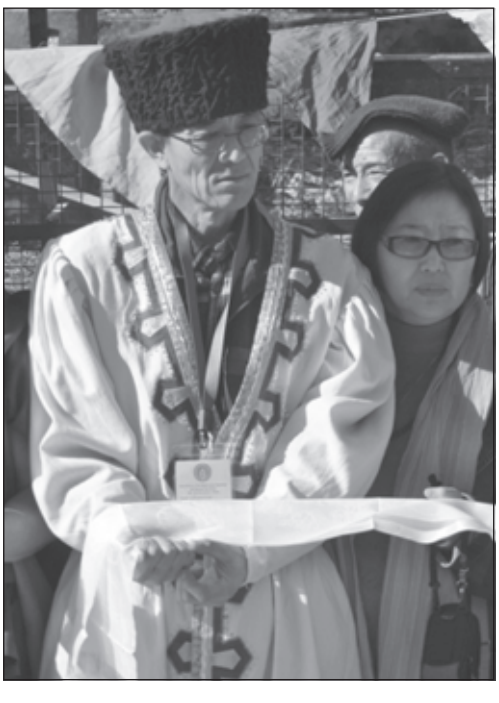

कैमरे की

1. तिब्बत में प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा दिए जाने के विरोध में अमेरिक
2. 18 नवंबर को दलाई लामा की रोम यात्रा के दौरान बार्सिलोना फुटबाल क
3. धर्मशाला में सिंगापुर के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए तीन दिवसीय विशेष उप
4. चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा ने भारत सरकार के सहयोग से अ
5. अपनी अरुणाचल प्रदेश यात्रा के दौरान दलाई लामा तावांग भी गए। वहां
6. ल्हासा में चीनी सेना की मौजूदगी में स्थानीय तिब्बती नागरिक एक मुख्य
7. 26 नवंबर 2008 के मुंबई के आतंकवादी हमले की पहली वर्षगांठ पर धर्म
8. रोम में तिब्बत समर्थक सांसदों के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान क
9. 10 अक्तूबर के दिन लोअर धर्मशाला के तिब्बती चिल्ड्रंस विलेज ने अपनी
10. 24 से 26 नवंबर के बीच रूसी बौद्धों के लिए दलाई लामा ने धर्मशाला में

♦ आंखों देखी

आंख से

का के शिकागो में 7 नवंबर को चीनी वाणिज्य दूतावास के सामने प्रदर्शन हुआ।
क्लब ने उन्हें अपना प्रतीक चिन्ह भेंट किया।
देश के दौरान दलाई लामा।
अरुणाचल की यात्रा की। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री खांडू के साथ ईटानगर में।
ं से लौटने पर वह हैलिकाप्टर से लोगों का अभिवादन लेते हुए।
मंदिर का चक्कर लगाते हुए।
शाला में तिब्बती और भारतीय लोगों ने मौन जुलूस निकाला।
वहां की संसद के सामने तिब्बती सांसद और हालिवुड अभिनेता रिचर्ड गेअर।
25वीं सालगिरह मनाई।
ं एक विशेष उपदेश दिया। इस अवसर पर कुछ रूसी बौद्ध श्रद्धालू।

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

आतंक के साए में चीनी वर्षगांठ

चीन सरकार ने साठवीं वर्षगांठ से पहले तिब्बत को विदेशियों के लिए बंद किया

बीजिंग, 20 सितंबर चीन ने कम्युनिस्ट शासन की 60वीं वर्षगांठ से पहले तिब्बत को विदेशियों के लिए बंद कर दिया और बीजिंग की सड़कों पर मशीनगनधारी सैनिक तैनात कर दिए। यहां तक कि राजधानी में पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

हालांकि 1 अक्तबूर को होने वाले समारोह बीजिंग केंद्रित हैं पर इसके बावजूद दूरदराज तक के इलाकों में सुरक्षा की चाक–चौबंद व्यवस्था की गई है। समारोहों में राष्ट्रपति हु जिंताओ द्वारा एक विशाल सैन्य परेड की सलामी लेना और भाषण देना शामिल हैं।

परेड मार्ग पर बने डिप्लोमैटिक अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वे परेड के दौरान न तो अपनी खिड़कियां खोलें और न ही बाल्कनी पर आएं। छुरी की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। अपार्टमेंट्स की लाबियों में नोटिस चिपका दिए गए हैं जिनमें लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध चीज की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।

ऑनलाइन संवेदनशील राजनैतिक विषयों और ट्विटर तथा फेसबुक सरीखे सोशल नेटवर्किंग साइटों को ब्लॉक कर दिया गया है। विदेशी पत्रकारों को भेजे जा रहे स्पाईवेयरयुक्त ई–मेल को नियंत्रित किया गया है। देशभर के कम्युनिस्ट अधिकारियों से कहा गया है कि वे लोगों को शिकायत लेकर बीजिंग न आने दें और मामले को स्थानीय स्तर पर निपटाएं।

राजधानी में पिछले साल के बीजिंग ओलिंपिक से भी अधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मशीनगन लिए सैनिक चारों तरफ गश्त लगा रहे हैं। हवाई खतरे के कारण शहर में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परेड मार्ग पर बने डिप्लोमैटिक अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वे परेड के दौरान न तो अपनी खिड़कियां खोलें और न ही बाल्कनी पर आएं। छुरी की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। अपार्टमेंट्स की लाबियों में नोटिस चिपका दिए गए हैं जिनमें लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध चीज की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। गौरतलब है कि हाल में शिंजियांग और पिछले साल तिब्बत में हिंसक घटनाएं हुई थीं। जुलाई में शिंजियांग की राजधानी उरुम्ची में भड़के जातीय दंगों में लगभग 200 लोग मारे गए थे। इसके अलावा, हाल में इस तुर्की मुस्लिम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर सुइयों से रहस्यमय हमले हुए थे जिसके कारण यहां तनाव बना हुआ है।

मार्च 2008 में तिब्बत में हुए दंगों के बाद वहां पर्यटकों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ल्हासा के दंगों में चीनी दुकानों और अप्रवासियों को निशाना बनाया गया था। गौरतलब है कि 1950 में तिब्बत में कम्युनिस्ट सैनिकों के घुसने के बाद वहां बड़ी संख्या में हान चीनी आकर बस गए।

तिब्बत चाइना ट्रैवल सवस में सेल्समैन सू तिंगुई के मुताबिक, अधिकारियों ने बीजिंग और ल्हासा में विदेषियों को तिब्बत के लिए विशेष परमिट देना बंद कर दिया है। ल्हासा में शेराटन होटल के पास स्थित फोर पॉइंट्स की एक रिसेप्शनिस्ट वांग ने कहा, ''अक्तूबर में कारोबार पर निश्चित रूप से बहुत असर पड़ेगा। इस महीने सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस और सैनिक दिखने लगे हैं। जिन चौराहों पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां भी पुलिसकर्मी और सैनिक तैनात कर दिए गए हैं।''

पिछले साल बीजिंग ओलिंपिक से हफ्तों पहले तिब्बत में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। फिर इस साल फरवरी और मार्च में संवेदनशील वर्षगांठों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक–चौबंद कर दी गई। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि शिंजियांग के दंगों के बाद तिब्बत के पर्यटन में और भी गिरावट आ गई। उरुम्ची के होटल भी खाली पड़े हैं।

तिब्बत टूरिज्म ब्यूरो में बिजनेस प्रशासन कार्यालय के एक अधिकारी तान लिन के मुताबिक, नए पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन जो पहले आ गए हैं, उन्हें ठहरने की इजाजत दी जाएगी।

चाइना इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॅन्टेम्पोरेरी इंटरनेशनल रिलेशंस में दक्षिण एशिया कार्यालय के प्रभारी हु शिशेंग के मुताबिक, सरकार ने इस आशंका के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया है कि विदेश स्थित तिब्बती समर्थक संगठन छात्रों या पर्यटकों के जरिए विरोध प्रदर्शन करवा सकते हैं। बीजिंग ओलिंपिक के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। चीन का कहना है कि तिब्बत और शिंजियांग में हिंसा के पीछे इन्हीं संगठनों का दिमाग था। लेकिन अधिकारियों ने सबूत के नाम पर कुछ नहीं मुहैया कराया है।

सिटी युनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के प्रोफेसर जोसेफ चेंग के मुताबिक, बीजिंग और अन्य जगहों पर आतंक पैदा करने वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन चीनी अधिकारियों का मानना है कि एक मजबूत और स्थायी राष्ट्र की छवि पेश करते हुए छोटी से छोटी घटनाओं को रोकना उनका फर्ज है। चेंग ने कहा, ''पिछले एक या दो साल में ओलिंपिक की तैयारी के दौरान चीन का सर्वोत्तम चेहरा दिखाने पर जोर था।'' उनके मुताबिक, स्थानीय सरकारी और सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों से कहा गया था, ''हम किसी तरह की घटना नहीं चाहते। अगर कुछ होता है तो आप लोग संकट में पड़ जाएंगे।''

अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले पर चीनी नियंत्रण की कोशिश नाकाम

मेला निदेशक ने चीनी दखल का माकूल जवाब दिया

फ्रैंकफुर्त, 18 सितंबर विश्वविख्यात फ्रैंकफुर्त बुक फेयर (एफबीएफ) में चीन सरकार ने अपनी तरह से सेंसरशिप लगाने की कोशिश की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई है। मेले के निदेशक ने कहा है कि इस साल के मेले में 'सेंसरशिप' नहीं होगी। उनका दावा है कि आयोजकों के सेंसरशिप में शामिल होने की खबर 'गलत' है।

एफबीएफ ने पहले चीनी 'असंतुष्ट' लेखकों––बेई लिंग और दाई किंग––को मेले के मुख्य अतिथि के रूप में चीन से संबंधित एक गोश्ठी में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा था। लेकिन बाद में उसने निमंत्रण को रद्द करने का फैसला किया जिसकी व्यापक आलोचना हुई। अपनी आलोचना के बाद एफबीएफ ने दोनों लेखकों को संगोश्ठी में आने की इजाजत दे दी जिसके कारण अधिकृत चीनी प्रतिनिधिमंडल ने संगोश्ठी का बहिश्कार कर दिया। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने मेले के आयोजकों से माफी भी मांगने के लिए कहा। लेकिन जुएरजेन बूस ने कहा है कि लेखकों को आने से रोकने का फैसला 'गलत' था। उन्होंने कहा, ''फ्रैंकफुर्त बुक फेयर अभिव्यक्ति की आजादी से समझौता नहीं करता। संवाद को सुगम बनाना आसान नहीं है। हम इससे हमेशा वाकिफ रहे हैं और गोष्ठी से भी इसकी पुष्टि होती है। बहरहाल, विवादों को सुलझाने के लिए एकमात्र सही रास्ता बातचीत का है।''

बूस ने कहा कि इस साल के मेले में कई विवादास्पद लेखकों के भाग लेने की उम्मीद है। उनमें चीनी नोबेल पुरस्कार विजेता गाओ सिंगजियान, जिनकी किताबें चीन में प्रतिबंधित है, और कवि यान लियान शामिल हैं। यह एफबीएफ के खुलेपन का प्रमाण है। मेले में वर्ल्ड उइगुर कांग्रेस के अध्यक्ष, आटस्ट अई वेईवेई, पत्रकार सुइ सिनरान, हांगकांग के लेखक लिउंग पिंग–क्वान और ताईवानी लेखक चांग ता–चुन के भी भाग लेने की उम्मीद है।

चीन को मिसाल के रूप में लेते हुए मेले में अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी पर चर्चा की जाएगी। कई कार्यक्रमों में तिब्बत पर भी चर्चा होगी।

बूस ने कहा, ''हम विविध और स्पष्ट विचारों के लिए मंच तैयार करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य संवाद कायम करना है। इसके कारण हमारे ऊपर सभी पक्षों का दबाव पड़ता है, लेकिन हम अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटेंगे। यह दबाव रचनात्मक सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रेरणा का काम करेगा। हमारा लक्ष्य अधिकृत चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ–साथ दुनियाभर के लेखकों, विद्वानों और बुद्जीवियों से संवाद बनाना है। हम चीन के साहित्य और संस्कृति पर निष्पक्ष रूप से चर्चा करेंगे।''

जर्मनी में चीन के राजदूत रहे मेई झाओरोंग ने पिछले हफ्ते के बहिष्कार के बाद जर्मनी में जर्मन अखबारों से कहा कि जर्मन आयोजकों ने चीनी प्रतिनिधिमंडल को बिना बताए गोष्ठी का कार्यक्रम बदल दिया। उन्होंने कहा, ''हम यहां लोकतंत्र का सबक सीखने नहीं आए हैं। सबक सीखने का समय बीत चुका है।''

लेकिन बूस अपने विचारों पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमेशा विवाद रहा है। सप्ताहांत का स्कैंडल मुख्य अतिथि चीन के सामने आने वाले लोकतांत्रिक विवाद की महज शुरुआत है। फ्रैंकफुर्त बुक फेयर लोकतंत्र का सबक देने नहीं जा रहा है लेकिन वह निश्चित रूप से लोकतंत्र का पैरोकार है।''

दलाई लामा ने प्राग में चेक प्रधानमंत्री से भेंट की

धर्मशाला, 12 सितंबर, फायुल परमपावन दलाई लामा ने कहा है कि निष्पक्ष सूचना, शिक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की कुंजी हैं। वे प्राग में फोरम 2000 फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे। कॉन्फ्रेंस का विषय था : ''एशिया में शांति, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार''। उन्होंने कहा कि जब स्वेच्छाचारी हुकूमतें अपनी ही जनता की इच्छा के खिलाफ बल का इस्तेमाल करती हैं तो उसके प्रतिकूल नतीजे निकलते हैं। इसलिए, एकमात्र रास्ता बातचीत का है। दलाई लामा ने, जिन्हें 1989 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, कहा, ''21वीं सदी में दुनिया का रुझान शांति, लोकतंत्र, खुलेपन, बातचीत और समझौते की तरफ है।''

निर्वासित उइगुर नेता रेबिया कदीर ने अपने खिलाफ चीन सरकार के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, '' चीन के नेता मुझ पर और उइगुर जनता पर आतंकवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने बैठी हूं। मैं आतंकवादी नहीं हूं।'' उन्होंने चीन सरकार पर आरोप लगाया कि वह चीनी जनता के दिमाग में उइगुरों के खिलाफ घृणा पैदा कर रही है। साथ ही कदीर ने यह भी कहा, ''हम

जर्मनी में चीन के राजदूत रहे मेई झाओरोंग ने पिछले हफ्ते के बहिष्कार के बाद जर्मनी में जर्मन अखबारों से कहा कि ''हम यहां लोकतंत्र का सबक सीखने नहीं आए हैं। सबक सीखने का समय बीत चुका है।'' लेकिन मेला आयोजक बूस ने कहा, ''लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमेशा विवाद रहा है। फ्रैंकफुर्त बुक फेयर लोकतंत्र का सबक देने नहीं जा रहा है लेकिन वह निश्चित रूप से लोकतंत्र का पैरोकार है।''

चीनी जनता के खिलाफ नहीं हैं।''

परमपावन दलाई लामा ने यूरोपीय संघ की तर्ज पर एशियाई संघ या क्षेत्रीय संघ बनाने की पैरवी की।

चेक के पूर्व राष्ट्रपति वाक्लाव हैवेल ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य चीन, तिब्बत, शिंजियांग, उत्तरी कोरिया, बर्मा और अन्य देशों में लोकतंत्र और आजादी के लिए लड़ने वालों का समर्थन करना है।

इस कॉन्फ्रेंस की पहल नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लेख वालेसा, शिरीन एबदी, फ्रेडरिक विलेम डि क्लार्क, अडोल्फो पेरेज एस्किीवेल और परमपावन दलाई लामा ने की। दलाई लामा ने पिछले साल कहा था कि एशिया में विकास के लिए गंभीर बातचीत की जरूरत है।

दलाई लामा के जिनेवा स्थित प्रतिनिधि त्सेतेन साम्दुप छोक्यापा के अनुसार दलाई लामा ने शाम को चेक प्रधानमंत्री से उनके आवास पर भेंट की। लेकिन बातचीत का ब्योरा नहीं मालूम हो सका।

ब्रिटिश मंत्री ने तिब्बत के लिए 'अधिक स्वायत्तता' का समर्थन किया

लंदन, 12 सितंबर एक ब्रिटिष मंत्री ने पिछले हफ्ते अपनी अप्रत्याशित ल्हासा यात्रा के दौरान कहा कि लंदन वृहत्तर तिब्बती स्वायत्तता का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस मंत्री ने बीजिंग में भी इस समर्थन को दोहराया।

कनिष्ठ विदेश मंत्री इवान लेविस सोमवार से गुरुवार तक चीन की यात्रा पर थे। वे तिब्बत में पिछले साल चीनी दमन के बाद वहां जाने वाले ब्रिटिश सरकार के पहले सदस्य थे। चीनी दमन की अंतरराष्ट्रीय समुदाय में तीखी आलोचना हुई थी। मार्च 2008 की घटनाओं पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने गंभीर चिंता भी व्यक्त की थी। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, लेविस ने कहा, ''यह मेरी ऐतिहासिक यात्रा है। मैंने यह यात्रा ब्रिटिश नीति में बदलाव के फैसले के सिलसिले में की है।''

लेविस ने आगे कहा, ''हम तिब्बत को चीन का स्वायत्त क्षेत्र मानते हैं। लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता मानवाधिकारों के सम्मान और वृहत्तर स्वायत्तता से ही कायम की जा सकती है। यह तभी संभव है जब चीन सरकार और (निर्वासित तिब्बती नेता) दलाई लामा के प्रतिनिधियों के बीच ठोस बातचीत हो। चीन ने कहा है कि तिब्बत की स्वतंत्रता को छोड़ किसी भी मसले पर बातचीत हो सकती है। मैंने उनसे अपील की है कि वे अपने शुरू के नजरिए को फिर से अपनाएं।''

लेविस ने तिब्बत में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और द्रेपुंग मठ के चेयरमैन से भेंट की। बीजिंग में उन्होंने युनाइटिड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के उपमंत्री से तिब्बत की स्थिति पर चर्चा की।

लेविस की यात्रा से पहले तिब्बती आंदोलनों के नेताओं ने उनसे अपील की थी कि वे हिमालय क्षेत्र में चीन के शासन के खिलाफ बोलें। इन नेताओं का कहना था कि पिछले साल की अशांति के बाद इस क्षेत्र में मानवाधिकार हनन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चीन के अधिकारियों का कहना है कि तिब्बती 'दंगाइयों' ने मार्च 2008 की अशांति के दौरान 21 लोगों को मार डाला। लेकिन निर्वासन में रह रहे संगठनों का दावा है कि चीनी सुरक्षा बलों ने तिब्बती प्रदर्शनों को कुचलने के लिए 200 से अधिक तिब्बतियों को मार डाला था।

सं. रा.मानवाधिकार आयुक्त ने तिब्बती उइगुर मामलों में चीन की निंदा की

तिबेतन रिव्यूडाटनेट, 17 सितंबर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की आयुक्त सुश्री नवनीतम पिल्लै ने कहा है कि ''भेदभाव और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा में विफलता के कारण चीन शासित पूर्वी तुर्कीस्तान और तिब्बत में हाल की हिंसक घटनाएं हुईं। पिल्लै ने यह टिप्पणी जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) को भेजी गई अपनी 'अद्यतन रिपोर्ट' में की है। रिपोर्ट 15 सितंबर को भेजी गई। उन्होंने कहा कि अधिकारों के हनन का मुख्य कारण लोकतंत्र का अभाव है।

लंबे समय के बाद एचआरसी ने चीन में मानवा धिकारों की हालत पर इतनी बेबाक टिप्पणी की है। इससे पहले कई साल से चीन इस परिषद में चीन में मानवाधिकारों की हालत पर बहस होने को लगातार रोकता आ रहा है। इस वोट में भारत भी पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन का समर्थन करता आया है।

पिल्लै ने कहा, ''मैंने शिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र की हाल की गड़बड़ियों पर बारीक नजर रखी। इससे पहले मैंने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और उसके इर्दगिर्द के इलाकों में फैली अशांति पर भी नजर रखी थी। मैंने इस तरह की हिंसा की भर्त्सना की और चीनी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे कानून बनाए रखने के लिए मानवाधिकारों का सम्मान करें। मैंने उन्हें इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया वे इस तरह की घटनाओं के मूल कारणों में जाएं। ऐसी घटनाओं के पीछे भेदभाव और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा न कर पाना शामिल है।''

पिल्लै ने अपनी रिपोर्ट में 'भेदभाव का कलंक'

पिल्लै ने कहा, ''मैंने शिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र की हाल की गड़बड़ियों पर बारीक नजर रखी। इससे पहले मैंने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और उसके इर्दगिर्द के इलाकों में फैली अशांति पर भी नजर रखी थी। मैंने इस तरह की हिंसा की भर्त्सना की और चीनी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे कानून बनाए रखने के लिए मानवाधिकारों का सम्मान करें। मपाना शामिल है।''

शीर्षक के तहत उइगुरों और तिब्बतियों की दुर्दशा का ब्यौरा दिया है।

जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत श्री ली बाओदोंग ने उच्चायुक्त पर ''तथ्यों की अनदेखी करने'' का आरोप लगाया। वे चाहते थे कि सुश्री पिल्लै उनकी सरकार की इस बात का समर्थन करें कि चीन के दोनों क्षेत्रों में विरोधी और अलगाववादी शक्तियों ने हिंसा भड़काई और आपराधिक कृत्य किए। उनका कहना था कि चीन सरकार की जातीय नीति के कारण दोनों क्षेत्रों में हिंसा नहीं फैली।

ली ने कहा कि पूर्वी तुर्कीस्तान और तिब्बत की घटनाएं मानवाधिकारों से संबंधित नहीं है। उन्होंने उच्चायुक्त की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने ''तथ्यों की उपेक्षा करते हुए कई प्रभुसत्ता–संपन्न राज्यों पर उंगली उठाई।''

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (सीईआरडी) ने 2008 में तिब्बती पठार में हुए विरोध प्रदर्शनों और इस साल जुलाई में पूर्वी तुर्कीस्तान में फैली हिंसा के मूल कारणों का पता लगाने के लिए चीन से अपील की थी। समिति ने चीन से यह भी अनुरोध किया था कि वह अंतर्जातीय हिंसा सहित इस तरह की घटनाओं के मूल कारणों पर गंभीरता से विचार करे और स्थिति के बदतर होने की वजहों का पता लगाए। समिति के इस अनुरोध के तीन हफ्ते बाद सुश्री पिल्लै की रिपोर्ट आई।

चीन ने राज्यों की प्रभुसत्ता बनाम मानवाधिकार का मुद्दा भी उठाया था। इस संबंध में सुश्री पिल्लै का कहना था कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकारों को अधिकार तो दिए ही गए हैं, जिम्मेदारी भी दी गई है। इसलिए, मानवाधिकारों का हनन रोकना उनका काम है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों से वंचित लोग और अन्य देश तथा संस्थाएं मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए परिषद की तरफ देखती हैं। उन्हें किसी भी हालत में निराश नहीं किया जाना चाहिए।

सुश्री पिल्लै ने कहा कि लोकतंत्र के अभाव के कारण ही मानवाधिकारों का सम्मान नहीं होता। उन्होंने कहा, ''जाहिर है, जब शासन की लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त और जिम्मेदार नहीं होतीं, जब कानून का शासन वास्तविकता के बजाय आकांक्षा तक सीमित रहता है और जब भ्रष्टाचार, असहयोग तथा दबाव का बोलबाला होता है तो मानवाधिकार के रक्षक महफूज नहीं रह सकते।''

मानवाधिकार परिषद का 12वां अधिवेशन 14 सितंबर से 2 अक्तूबर तक पैलेस डेस नेशंस, जिनेवा में चला।

दलाई लामा को फ्रीडम अवार्ड

मेम्फिस के समारोह में रिचर्ड गेअर ने दलाई लामा पर बना वृत्तचित्र पेश किया

माईफॉक्समेम्फिस.कॉम, 23 सितंबर मेम्फिस, टेन। नेशनल सिविल राइट्स म्युजियम बोर्ड के सदस्य जे. आर. 'पिट' हाइड ने जब घोषणा की कि ''इंटरनेशनल फ्रीडम अवार्ड के विजेता परमपावन दलाई लामा हैं'' तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

भारत में 50 वर्षों से निर्वासन में रह रहे दलाई लामा ढेरों पुरस्कार और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद झूठी विनम्रता में विश्वास नहीं करते। इसीलिए अहिंसा, आत्मिक शांति और प्रेम का उनका संदेश उनके देश की सीमाओं से परे आज भी गूंजता है। तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के बाद दलाई लामा और 100,000 से अधिक अन्य तिब्बती भागकर भारत आ गए थे।

परमपावन के सम्मान में पीबॉडी में लंच का आयोजन किया गया। इस मौके पर आध्यात्मिक नेता ने बहुत विनम्रता से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ''मैंने मानवता के कल्याण में जो थोड़ा–बहुत योगदान किया है, मेरे ख्याल से इस पुरस्कार के जरिए उसे मान्यता दी गई है।''

समारोह के दौरान एक वृत्तचित्र भी दिखाया गया। अभिनेता रिचर्ड गेअर ने वृत्तचित्र का परिचय देते हुए उस शख्स के असामान्य जीवन पर रोशनी डाली जो चार साल की उम्र में लाखों तिब्बतियों की आध्यात्मिक प्रेरणा बन गया था। सन् 1959 से स्थायी निर्वासन में रहते हुए भी दलाई लामा तिब्बतियों को खाना और बसेरा मुहैया कराकर उनकी सेवा कर रहे हैं। वे तिब्बतियों की आजादी की लड़ाई और उनके मानवाधिकारों के संघर्ष में शामिल हैं। उन्होंने 70 किताबें लिखकर अपने शांति के दर्शन को दुनियाभर में फैलाया है। इन किताबों में उन्होंने प्रेम और करुणा का संदेश दिया है।

अपने संवाददाता सम्मेलन में दलाई लामा ने कहा, ''अगर आपका दिमाग खुला है, करुणा और प्रेम से भरा है तो आपकी पूरी सोच सकरात्मक हो सकती है।'' अपनी कहानी में वेदना होने के बावजूद वे परिहास करने से नहीं चूकते। कुछ लोगों को अपना स्कार्फ देते हुए उन्होंने चुटकी ली ''मैं अपना यह स्कार्फ सद्भाव के प्रतीक के रूप में भेंट करता हूं। स्कार्फ की परंपरा भारत की है, लेकिन यह चीन में बना है।''

अभिनेता रिचर्ड गेअर ने वृत्तचित्र का परिचय देते हुए उस शख्स के असामान्य जीवन पर रोशनी डाली जो चार साल की उम्र में लाखों तिब्बतियों की आध्यात्मिक प्रेरणा बन गया था। सन् 1959 से स्थायी निर्वासन में रहते हुए भी दलाई लामा तिब्बतियों को खाना और बसेरा मुहैया कराकर उनकी सेवा कर रहे हैं। वे तिब्बतियों की आजादी की लड़ाई और उनके मानवाधिकारों के संघर्ष में शामिल हैं।

दलाई लामा ने मार्टिन लूथर किंग के हत्यास्थल पर प्रार्थना की

अन्याय और असमानता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में आस्था व्यक्त की

मेम्फिस, टेनेस्सी, 23 सितंबर निर्वासन में रह रहे तिब्बत के पूर्व शासक और आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने उस स्थल पर जाकर प्रार्थना की जहां 1968 में अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या की गई थी।

74 वर्षीय भिक्षु दलाई लामा पहली बार मेम्फिस आए थे। यहां नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम ने उन्हें फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया। अवार्ड पर उस लोरेन मॉटल का चित्र खुदा है जहां माटन लूथर किंग की गोली मार कर हत्या की गई थी।

दलाई लामा ने हत्यास्थल पर माला रखने के बाद उस पर सफेद स्कार्फ भी चढ़ाया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''यह बहुत मर्मस्पर्शी यात्रा है। यहां की ऐतिहासिक घटनाएं हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''हर जगह के लोग अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष करते हैं। लेकिन हम इन संघर्षों में हर तरह की मुश्किलों और बाधाओं के बावजूद जीत सकते हैं।''

चीन सरकार दलाई लामा की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का लगातार विरोध करती रही है। वह उन पर 'अलगाववादी' होने का आरोप लगाती है। लेकिन दलाई लामा का कहना है कि वे चीनी हुकूमत के कब्जे में रहने वाले तिब्बतियों के लिए और अधिक अधिकार चाहते हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बाराक ओबामा ने दलाई लामा से मिलने के लिए अपना एक उच्च स्तरीय अधिकारी मंडल धर्मशाला भेजा था।

मेम्फिस में दलाई लामा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया जहां उन्होंने इंटरनेशनल फ्रीडम अवार्ड स्वीकार किया। अपने सम्मान में दिए गए लंच के बाद उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से 2,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया।

म्युजियम के चेयरमैन बेंजामिन हुक्स ने कहा, ''डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर और गांधी की अहिंसा के जीवित उदाहरण दलाई लामा बर्बरता और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने राजनैतिक दमन और कष्ट के बावजूद अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा है। आज जबकि तिब्बती अपने निर्वासन के 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं, दलाई लामा का संघर्ष हर जगह सामाजिक न्याय के आंदोलनों के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है।''

म्युजियम के चेयरमैन बेंजामिन हुक्स ने कहा, ''डॉ. मार्टिन लूथर किंग और गांधी की अहिंसा के जीवित उदाहरण दलाई लामा बर्बरता और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने राजनैतिक दमन और कष्ट के बावजूद अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा है। आज दलाई लामा का संघर्ष हर जगह सामाजिक न्याय के आंदोलनों के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है।

तिब्बती भिक्षुओं ने मौसम परिवर्तन पर विश्व दिवस में भाग लिया

धर्मशाला, फायुलडॉटकॉम, 21 सितंबर तिब्बत सरकर के राजकीय भविष्यवक्ता और ओझा नेचुंग दोर्जेचांग की पीठ नेचुंग मठ के तिब्बती भिक्षुओं ने मौसम परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई विश्व दिवस में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि जी–20 शिखर सम्मेलन से पहले दुनिया के नेताओं को मौसम परिवर्तन के खिलाफ चेताने के लिए विश्व पहल की जा रही है। मठ के वरिष्ठ भिक्षुओं ने मनुष्य जाति में दूसरों प्रणियों और प्रकृति के प्रति करुणा जगाने के लिए विशेष अवलोकीतेश्वर पूजा की। भिक्षुओं ने तुरही बजाकर मौसम परिवर्तन के खिलाफ विश्व कार्रवाई के लिए दुनिया का सांकेतिक आह्वान किया। कनिष्ठ भिक्षु अपने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए थे जिन पर लिखा थाः ''कार्बनडाई ऑक्साइड में कटौती कर 350 पीपीएम पर लाओ, तिब्बत को बचाओ'', ''दुनिया के लोगों जागो और पृथ्वी को बचाओ'', ''दुनिया के नेताओं जागो, मौसम परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करो''।

एक वरिष्ठ भिक्षु नावांग ने कहा कि तिब्बत, जिसे 'तीसरा ध्रुव' और 'एशिया का वाटर टॉवर' कहा जाता है, मौसम परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने की चुनौती से जूझ रहा है।

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चैंज (आईपीसीसी) के मुताबिक, हिमालय के हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बाढ़ आएगी और सूखा पड़ेगा।

तेसी एनवायरनमेंट अवेयरनेस मूवमेंट की त्सेरिंग यांकी ने कहा कि हिमनद और बर्फ बहुत कम रफ्तार से जम रहे हैं और तेज रफ्तार से पिघल रहे हैं। ''इन हिमनदों के बिना नदियों का बहाव मौसमी हो जाएगा जिससे लाखों लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा। दुर्भाग्य से चीन की उपनिवेशवादी भूख ने इस हालत को और बिगाड़ा है।''

विशेषज्ञों का कहना है कि तिब्बती पठार एशियाई मानसून को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। मानसून की तीव्रता कम हो गई है। तिब्बती पठार एशिया के मौसम के बैरोमीटर के रूप में काम करता है।

बुद्ध, गांधी और दलाई लामा के शांति संदेश की भक्ति संगीत से स्मृति

बुद्ध जयंती पार्क में बुद्ध प्रतिमा की 16वीं वर्षगांठ पर संगीतमय समारोह

हर साल की तरह इस बार भी नई दिल्ली के तिब्बत हाऊस ने दो अक्तूबर के दिन बुद्ध जयंती पार्क में एक विशेष भक्ति संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पार्क में स्थापित बुद्ध प्रतिमा के सामने आयोजित किया गया। सोलह साल पहले इसी दिन परमपावन दलाई लामा की ओर से भेंट स्वरूप प्राप्त इस प्रतिमा को इस पार्क में स्थापित किया गया था। तब से हर साल तिब्बत हाऊस 2 अक्तूबर के दिन ऐसा कार्यक्रम आयोजित करता है।

कार्यक्रम के संयोजक और तिब्बत हाऊस के निदेशक भिक्षु दूबून रिंपोछे के अनुसार इस कार्यक्रम का लक्ष्य गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध और परमपावन दलाई लामा के शांति संदेश पर मन मंथन करना है।

इस कार्यक्रम के विशेष मेहमानों में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल डा. भीष्म नारायण सिंह और भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डा. जी वी जी कृष्णमूर्ति भी शामिल थे।

इस बार के कार्यक्रम की शुरूआत दिल्ली की मजनू का टीला तिब्बती बस्ती के न्गाकपा द्रात्सांग मठ के भिक्षुओं के गाए मंगलाचरण से हुई। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका विदुषी प्रिया कानूनगो का भक्ति गायन था। उन्होंने पहले संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों से कुछ सूत्रों का गायन किया। उसके बाद उन्होंने भारत की भक्ति परंपरा में कबीर और मीरा जैसे भक्ति कवियों के काव्य भंडार से कुछ भक्ति गीतों को स्वर दिया।

डा. प्रिया कानूनगो ने गायन में दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई और वह एक पत्रकार के रूप में भी काम करती हैं।

भारत–तिब्बत मैत्री संघ का आठवां राष्ट्रीय सम्मेलन देहरादून में संपन्न

भारत में तिब्बती आजादी के लिए चलने वाले आंदोलन के एक अग्रणी सदस्य भारत–तिब्बत मैत्री संघ का आठवां राष्ट्रीय सम्मेलन देहरादून में संपन्न हुआ। यहां क्लेमेंट टाउन की थुंडुनलिंग तिब्बती बस्ती के मिंडुलिंग मठ के सभाभवन में आयोजित इस सम्मेलन में भारत के कोने–कोने से आए तिब्बत समर्थक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और आंदोलन की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की।

31 अक्तूबर अैर 1 नवंबर को हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रसिद्ध गांधीवादी विद्वान और तिब्बत की निर्वासन सरकार के निर्वाचित प्रधानमंत्री प्रोफेसर सामदोंग रिंपोछे ने किया। सम्मेलन के प्रधान आयोजक और मैत्री संघ के महासचिव डा. आनंद कुमार की देखरेख में सम्मेलन का आयोजन किया गया।

सम्मेलन में भारत–तिब्बत–चीन संबंधों की वर्तमान चुनौतियों, चीन की तिब्बत और भारत के प्रति वर्तमान नीति, चीन के कारण हिमालय में उत्पन्न नए खतरों तथा हिमालय बचाओ–तिब्बत बचाओ अभियान पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस चर्चा में देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, महिलाएं, हिमालय क्षेत्र के बौद्ध भिक्षु और तिब्बत समर्थक संगल्नों और कार्यकर्ताओं ने उत्साह से भाग लिया। अगले वर्ष के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। आगामी अभियानों के बारे में प्रस्ताव भी स्वाकार किए गए।

(सम्मेलन पर विस्तृत रिपोर्ट और प्रस्तावों का विवरण 'तिब्बत देश' के अगले अंक में)

अरुणाचल मुख्यमंत्री ने दलाई लामा यात्रा के सवाल पर चीन को लताड़ा

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दोर्जी खांडू ने दलाई लामा की प्रस्तावित तावांग यात्रा के संदर्भ में चीन सरकार को चेतावनी दी है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप न करे। चीन सरकार का कहना है कि चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश विवाद का मुद्दा बना हुआ है इसलिए दलाईलामा को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चीन इस पूरे राज्य पर अपना दावा जताता है। इससे पहले राज्य के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर भी चीन के सरकारी प्रवक्ता ने बहुत ओछे स्तर की टिप्पणियां की थीं।

तिब्बत के पूर्व शासक और आध्यात्मिक नेता दलाई लामा नवंबर में प्रदेश की राजधानी इटानगर और तवांग मठ की यात्रा पर आने वाले हैं। दोर्जी खंडू ने फोन पर एएफपी से कहा, ''चीन को दलाई लामा की प्रस्तावित अरुणाचल प्रदेश यात्रा के मामले में

श्री दोर्जी खांडू ने दलाई लामा की प्रस्तावित तावांग यात्रा के संदर्भ में चीन सरकार को चेतावनी दी है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप न करे। चीन इस पूरे राज्य पर अपना दावा जताता है। इससे पहले राज्य के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर भी चीन के सरकारी प्रवक्ता ने बहुत ओछे स्तर की टिप्पणियां की थीं।

हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हम दलाई लामा की यात्रा का स्वागत करते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी यात्रा सफल हो।''

उल्लेखनीय है कि चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा 1,030 किमी लंबी है जिस पर बाड़ नहीं लगी है। भारत और चीन को मकमहोन रेखा अलग करती है। लेकिन वास्तविक सीमा या नियंत्रण रेखा के रूप में चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। भारत और चीन के बीच 1962 में लड़ाई भी हो चुकी है जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक हताहत हुए थे। उस दौरान चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में दूर तक घुस आए थे।

भारत के विदेष मंत्री एस.एम. कृष्णा ने हाल में चीन की आपत्ति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, ''अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग है और भारत के एक सम्मान मेहमान के नाते दलाई लामा इस देश में कहीं भी आने–जाने के लिए स्वतंत्र हैं।''

तिब्बत में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन पर भारत और चीन सहयोग को सहमत

नई दिल्ली, 29 अगस्त पर्यावरण और वन राज्य मंत्री जयराम रमेश ने यहां कहा कि भारत और चीन हिमालय एवं तिब्बती क्षेत्र की हिमनदियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन संयुक्त रूप से करेंगे। रमेश जलवायु परिवर्तन पर इस महीने के शुरू में चीन में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने चीन गए थे। उन्होंने कहा, ''हमने सहयोग पर बात कर ली है। भारत के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जिओलॉजी और चीन की कोल्ड ऐंड एरिड रीजंस एन्वायरनमेंटल ऐंड इंजीनियरिंग रिसर्च संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे।''

श्री रमेश भारत की सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित एक रिपोर्ट जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। रिपोर्ट भारतीय रक्षा अध्ययन एवं विश्लेशण संस्थान ने तैयार की है।

चूंकि दक्षिण एशिया की ज्यादातर नदियां तिब्बती पठार से निकलती हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन का इस क्षेत्र में विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। श्री रमेश ने कहा, ''चीन ने हिमनदी विज्ञान के अध्ययन के लिए मानव संसाधन के रूप में भारी निवेश किया है। हम तो अभी इस दिशा में शुरुआत कर रहे हैं। हमारी हिमनदियों को क्या हो रहा है, इसकी गहराई से पड़ताल के लिए संयुक्त अध्ययन बेहतर रहेगा।''

उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत और चीन के बीच सहयोग महज संयुक्त अध्ययन परियोजना तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने अमेरिका के स्वच्छ ऊर्जा एवं रक्षा अधिनियम का कड़ा विरोध किया है।

श्री रमेष ने कहा, ''हम (भारत और चीन) उस विधेयक को खारिज करते हैं और उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इस मुद्दे पर विकासशील देशों के बीच मतैक्य है। चीन की प्रतिक्रिया त्वरित थी और उसने जवाबी कदम उठाने की धमकी तक दे डाली।'' भारत दिसंबर में कोपेनहेगन में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेगा।

चीन में भारत 'दुश्मन नंबर–1' पर चीनी सेना की क्षमता पर आशंका

नई दिल्ली, 28 सितंबर ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच कटुता बढ़ती दिख रही है, एक ब्रिटिश अखबार का दावा है कि कई चीनी नागरिक भारत को अपना 'दुश्मन नंबर–एक' मानते हैं।

संडे टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी गणराज्य की 60वीं वर्षगांठ से पहले चीन में भारत को 'दुश्मन नंबर–एक' माना जा रहा है। हालांकि चीन मीडिया सेंसरशिप से संबंधित कड़े कानून के लिए जाना जाता है, लेकिन उसने तिब्बत मुद्दे पर भारत से दूसरी लड़ाई लड़ने के गुण–दोष पर चर्चा के लिए खुली छूट दी हुई है।

संडे टाइम्स ने एक सेवानिवृत्त चीनी अधिकारी को यह कहते हुए उद्धृत किया है कि चीन सेना के मामले में भारत से बीस हैइस पर संदेह है कि चीनी फौज लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। उसने इस पर भी संदेह व्यक्त किया कि जनमुक्ति सेना के सैनिक पहले जैसे ही देशभक्त हैं या नहीं। उसने यह भी कहा कि, ''भारत के खिलाफ 1962 की लड़ाई में हमारे हथियार बेहतर थे। लेकिन हमारे अफसरों की देश और जनता के प्रति निष्ठा बहुत बदतर है।''

रिपोर्ट के अनुसार, जनमुक्ति सेना को भीतर से जानने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों का कहना है कि इतने तामझाम के बावजूद वास्तविकता यह है कि चीनी फौज के पास हाल में लड़ने का कोई अनुभव नहीं है और वह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।

अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि किसी प्राइवेट सैनिक को अच्छे पद पर जाने के लिए 10,000 युआन (रु 70,000) और मिलिट्री कॉलिज में जगह पाने के लिए 30,000 युआन रिश्वत देनी पड़ती है। रिपोर्ट में एक राजनैतिक कामिसार जनरल झांग शुतिआन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, ''यदि फौज में भ्रष्टाचार जारी रहा तो विचारधारा क्षीण पड़ती जाएगी और धर्म के लिए रास्ता साफ होता जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, जनमुक्ति सेना को भीतर से जानने वाले सेवानिवृत्त अफसरों का कहना है कि इतने तामझाम के बावजूद वास्तविकता यह है कि चीनी फौज के पास हाल में लड़ने का कोई अनुभव नहीं है और वह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि किसी प्राइवेट सैनिक को अच्छे पद पर जाने के लिए 10,000 युआन (रु. 70,000) और मिलिट्री कॉलिज में जगह पाने के लिए 30,000 युआन रिश्वत देनी पड़ती है।